The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2, 3 *and the Schedule were added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I beg to move:

That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.

The Appropriation (No. 3) Bill, 2005

And

The Appropriation (No. 4) Bill, 2005.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I move:

> That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2005-06, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, I also move:

> That the Bill to provide for the authorisation of appropriation ofmoneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 2003, in excess of the amounts granted for those services and for that year, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, I come before this House for a further sanction to Rs. 14,661.36 crores. Details of supplementary demands are given in the document which has already been laid on the Table of the House. To the extent of Rs. 7842.28 crores, that is only technical demand, the enhanced provision is matched by savings of the concerned departments or by enhanced receipts and recoveries. An addition token provision of Rs. 52 lakhs has been sought, one lakh each item of expenditure for enabling reappropriation of savings involving new service and new instrument of service. Hence, the net cash outgo involved is only Rs. 6,818.56 crores. Now, the major heads of cash outgo are Rs. 5,222.48 crores for additional transfer to the State and

Union Territories. Of this, Rs. 1846.48 crores is Grants-in-Aid and Rs. 3,376 crores is Loans. Now, the Grants-in-Aid and Loans include monies given for additional Central assistance for the Accelerated Irrigation Benefit Programme and the Accelerated Power Development Programme. So, bulk of this money is not for my expenditure, it is for the expenditure of the States. Sir, Rs. 916.67 crores is for the Department of Telecommunications for Rural Telephony, including Rs. 300 crores for Universal Service Obligation Fund and Rs. 616 crores for BSNL for Rural Telephony. Sir, Rs. 500 crores is for the Delhi Metro Rail, Rs. 100 crores is for the Fast Track Courts and Rs. 73 crores is for payment of compensation to the Indian Airlines on account of old liabilities of Vayudhoot. All these Heads of expenditure came up or were finalised or the proposals were received and approved after 28th February, 2005. Therefore, they could not have been included in the Budget. Therefore, I am coming up with this first Supplementary. I request the House to grant them.

Sir, the Appropriation (No. 4) Bill, 2005, is for excess demands for the year ended 31st March, 2003, based on the final accounts. It is purely a technical thing.

The questions were proposed

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, अनुदानों की पूरक मांगों, 2005-06 का पहला बैच, पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा गया है। 6 महीने के अंदर ही यह मांग सदन के अंदर अनुमोदन के लिए आयी है। सामान्य तौर पर इतनी कम अवधि में आने का कोई औचित्य नहीं होता तो भी जैसा अभी वित्त मंत्री जी ने बताया कि जितना भी नेट आउटगो है, इसके लिए, सारी राशि आ गयी है और उसके पश्चात् ही यहां इसको अनुमोदन के लिए रखा गया है। तब भी जिस प्रकार की प्रक्रिया रही है, उसको देखने के पश्चात् यह लगता है कि वह कितना आ पाता है, कितना रहता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। सामान्य बजट के दौरान ही ये सारे अंक आ जाते तो ज्यादा उपयुक्त होता। ऐसा लगता है कि जिस तरीके से राजस्व घाटा बढ़ रहा है, राजकोषीय घाटे बढ़ रहे हैं, उसको देखकर शायद सामान्य बजट में इसलिए नहीं रखा गया होगा कि उससे घाटे में और बढ़ोतरी हो जाती और तत्काल 6 महीने के अंदर ही अनुदानों की पूरक मांगों के माध्यम से इसको अनुमोदित करवा लिया जाए, इस मंशा से प्रेरित होकर संभवतया यह अनुदान की पूरक मांग रखी गयी है। इसमें एक अपेक्षा थी। माननीय वित्त मंत्री जी ने यह बजट प्रस्तुत किया है और इसका अनुमोदन कराना चाहते हैं। अनुदानों की मांगों को पूरा करने की दृष्टि से बजट आता है, देश के अंदर ऐसी कोई विशेष घटना घटित होती है, प्राकृतिक

आपदा होती है, उसको, उस धनराशि को लेने की दृष्टि से अनुमोदन लेना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से सामान्य तौर पर इस प्रकार की मांगें आती हैं लेकिन इसको पूरा देखने के पश्चात् ऐसा कहीं दिखायी नहीं पड़ा है। स्वयं वित्त मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि कुछ ऐसे बड़े हेड्स हैं जिनमें ज्यादा पैसा, ज्यादा धन अनुमोदित करने की दृष्टि से रखा गया है, जैसे टेलीकम्यूनिकेशन मंत्रालय का उन्होंने कहा है, 900 करोड़ का, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारों के अंतरण के बारे में कहा है, 1,846.48 करोड़ का। चालू परियोजनाओं के बारे में कहा, 3,376 करोड़ का तथा दिल्ली मेट्रो रेल के बारे में 500 करोड़ का कहा है। ये सारे बड़े-बड़े हेड्स हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है जैसे आपने कहा कि टैक्निकल धनराशि 7,842.28 करोड़ की है। उसके माध्यम से इसमें दिया है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए 5,762.85 करोड़, इस माध्यम से लिया जाएगा, इसके अंतर्गत लिया गया है।

वह कैसे आएगा, पता नहीं। विद्युत मंत्रालय का है 1100 करोड़ का और फिर दिया है–राष्ट्रीय श्रम विकास योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को 3462.50 करोड़ का सहायता अनुदान दिया जाएगा। मान्यवर, ये सारी राशि दिखाई गई हैं और जब हम देखते हैं कि सामान्य बजट का जो स्वरूप रहा है, उसको देखने के पश्चात् मैं यह कह सकता हूं कि जो राजकोषीय घाटा है, वह कभी 4.4 का, 4.3 का, 4.5 का–इस तरीके से रहा है। वह घट नहीं रहा है, वह बढ़ता ही जा रहा है, जो बड़ा खतरनाक है। राजस्व घाटा भी जो ज्यादा बढ़ा है, उसमें 95,312 करोड़ का राजस्व घाटा बढ़ा है। राजस्व प्राप्तियां अपेक्षा के अनुरूप प्राप्त नहीं हुई हैं। जो अनुमान लगाया गया था राजस्व प्राप्तियों के लिए–3,17,733 करोड़ का, उसका संशोधित रूप जो आया है, उसमें 3,06,021 करोड़ का संशोधित आया है, जिसके अंदर 11,721 करोड़ कम आ रहा है, अर्थात् राजस्व प्राप्तियां अपने हिसाब से, जिस ढंग से अनुमान किया गया था, उतनी न आकर कम ही आ रही हैं। तो फिर होगा कैसे? कहीं न कहीं से कटौती की जाएगी और इसलिए बजट में जो पूरा दिया गया है, 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है और जैसे योजना व्यय में, 2004-05 में योजना व्यय था 82,529 करोड़ का, 2005-06 का जो योजना व्यय रखा गया, वह 1,10,386 करोड़ का था, इसमें 30,000 करोड़ की बढ़ोतरी रही है। जब पूरा सामान्य बजट देखा गया और अभी भी यहां यह बजट देखा गया, तो इसको देखने के पश्चात् यह दिखाई पड़ा कि राज्यों को जो केंद्रीय सहयोग प्राप्त होता था, उसमें से कटौती की गई है और उसमें से कटौती जैसे राज्यों को देनदारी के अंदर जो योजना सहायता राज्यों को दी गई थी 2004-05 में वह 54,858 करोड़ की थी और 2005-06 में 33,112 करोड़ की सहायता दी गई है। इसमें 21,748 करोड़ की कमी की गई है। जो पैसा दिया गया है, जो राज्यों को दिया जा रहा

सहयोग था–वह उसमें कटौती करके दिया गया है। यह जो 30,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, इस बढ़ोतरी में इसको भी जोड़ दिया जाए, तो लगभग 44,000 करोड़ तक कि स्थिति आ जाती है। परिणाम यह होगा कि राजस्व घाटा और तेज़ी के साथ बढ़ेगा। राजकोषीय घाटा भी बढ़ता जाएगा, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण आर्थिक व्यवस्था चकनाचूर हो सकती है। जैसे राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए जब हम कर्ज़ा लेते हैं, उस कर्ज़े का ब्याज 2004-05 का 1,22,905 करोड़ का था और 2005-06 में 1,33,945 करोड़ का है। मान्यवर, 8040 करोड़ यह बढ़ा हुआ है। निरंतर इसकी बढ़ोतरी होती जाएगी और जब बढ़ोतरी होती जाएगी, तो उसके लिए, अनेक तरीकों से, आम जनता के ऊपर बजट का बोझ बढ़ाना ही पड़ेगा और बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। प्रधान मंत्री जी ने और महामहिम राष्ट्रपति जी ने स्वयं अपने भाषणों में उल्लेख किया है और स्वयं आपने, अपने बजट भाषण में भी दिया था, भारत निर्माण की बात कही गई थी और भारत निर्माण के बारे में बड़े सुनहरे सपने दिखाए गए हैं, जिसके आधार पर लगता है कि सचमुच जिस तरीके से योजना बनाई गई है, इसको कार्यान्वित कर दिया जाएगा और एक ऐसी स्थिति का निर्माण होगा कि कोई आदमी गरीब नहीं रहेगा। उसमें विशेषकर मूलभूत ढांचों के बारे में, आधारभूत ढांचों के बारे में कहा गया है। सड़क, बिजली, पानी, परिवहन, स्वास्थ्य–इन सारी चीज़ों के बारे में कहा गया है और उसके बारे में वित्त मंत्रालय में, इस सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, इसके लिए 1,74,000 करोड़ की योजना 2009 तक पूरा करने के लिए बनाई गई है। एक करोड़ हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। एक हजार की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने की बात है। पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र के पांच सौ की आबादी वाले गांवों में पक्के संपर्क मार्ग बनेंगे।

60 लाख मकान गरीबों को दिए जाएंगे, 74 हजार गांवों में शुद्ध पानी पहुंचाया जाएगा। 1 लाख 25 हजार गांवों में और 23 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई जाएगी। 66,882 गांवों में फोन पहुंचाया जाएगा। ये सारी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन ये घोषणाएं पूरी कहां से होंगी? ग्रामीण विकास मंत्रालय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। इसमें संचार मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय है, जल संसाधन मंत्रालय है। ये सारे मंत्रालय हैं। लेकिन उनकी आर्थिक हालत क्या है? बजट की स्थिति क्या है? वित्त मंत्रालय ने रुटिन के हिसाब से वार्षिक बजट में पैसा दिया है। इसके अतिरिक्त जो धन की आवश्यकता है, इसके लिए वित्त मंत्रालय तैयार नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको पूरा करने के लिए स्वयं 96 हजार करोड़ रुपए की मांग की है। लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस पर साफ इंकार कर दिया है। इतना ही नहीं, पिछली बार 18 हजार करोड़ ग्रामीण विकास मंत्रालय

के लिए तय था। अभी भी पिछले वर्ष का 15 हजार 500 करोड़ बकाया है। लगभग साढ़े तीन हजार या ढ़ाई हजार करोड़ केवल मात्र खर्च हुआ है या दिया गया है। बाकी का पैसा उपलब्ध नहीं है। इस वर्ष का जो बजट है, 24 हजार करोड़ रुपए का है और उनकी मांग 96 हजार करोड़ है। पिछले वर्ष का प्राप्त नहीं हुआ है। 24 हजार करोड़ में कितना प्राप्त होगा, पता नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से जो भारत निर्माण का सुनहरा स्वप्न है, कैसे पूरा करने की दिशा में कार्य करेंगे। गत वर्ष ग्रामीण सड़क योजना में 24 हजार करोड़ वार्षिक बजट रखा गया है जबकि नई योजना के हिसाब से 48 हजार करोड़ चाहिए। यह 48 हजार करोड़ कहां से देंगे? इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है। जब पिछला ही पूरा नहीं हुआ है तो बाकी का कहां से देंगे? मान्यवर, पेयजल के लिए 16 हजार करोड़ मिलना था। नई व्यवस्था के अंदर 41 हजार करोड़ चाहिए। हमने पहले ही आपको बताया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 96 हजार करोड़ मांगा है, 24 हजार करोड़ की बात कही गई है। लेकिन पिछला भी बकाया है यही स्थिति ऊर्जा विभाग कीं भी है। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 25 हजार गांव और 2.3 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाने की बात कही गई है। उन्होंने अलग से 9 हजार करोड़ रुपए की मांग की है, जबकि 8 हजार करोड़ की ही बात कही गई है। ऐसी स्थिति में चाहे महामहिम राष्ट्रपति हों, चाहे भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी हों, जिन्होंने लाल किले के मैदान में दिए गए भाषण के अंतर्गत बात कही, लेकिन यह सब पूरा कैसे होगा। आर्थिक स्रोत का निर्माण कहां से होगा? किस ढंग से पैसे आएंगे, इसका कही कोई जिक्र नहीं है और जो आंकड़े हैं, जो बजट है, इस बात को बताता है कि केवल मात्र घोषणाएं हैं और घोषणाएं करके लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की गई है। मान्यवर, आर्थिक सर्वे के आधार पर कुछ अर्थशास्त्रियों की टीम ने एक वैकल्पिक आर्थिक सर्वेक्षण किया है और उस वैकल्पिक आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि जो भारत सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति चल रही है, उसके कारण उदारीकरण और वैश्वीकरण के क्रम में आम जनमानस त्रस्त होगा, प्रतिवर्ष प्रतिस्पर्धा के क्रम में, गरीब किसान और गरीब होता जाएगा, गरीब आदमी और गरीब होता जाएगा और अमीर और अमीर होता जाएगा। मान्यवर, लोगों ने इस संबंध में अनेक उदाहरण देते हुए आंकड़े भी दिए हैं। आम आदमी की हालत अत्यधिक खराब होगी, इस सर्वेक्षण के माध्यम से बताया गया है। साथ ही साथ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन, इन्होंने भी एक सर्वे किया। उस सर्वे के आधार पर उन्होंने बताया है कि आधारभूत ढांचे की कमी के कारण आज हिन्दुस्तान का आम आदमी कितना परेशान है, उसको कोई उपलब्धता नहीं है। बिजली और पानी की बदहाली का तो बड़े व्यापक तौर पर उन्होंने वर्णन किया है। बिजली, पानी, परिवहन, संचार और सड़क इन सारी चीजों को लेकर वर्णन किया है।

आज भी आबादी के 48 प्रतिशत लोग साइकल पर चलते हैं और सर्वाधिक हादसे के शिकार होते हैं। सड़क भी अच्छी नहीं रहती, इसलिए उनकी दुर्दशा होती है। इसका उन्होंने बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 86 फीसदी लोग ऐसे हैं, जिनको शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं है, बिहार में 89 फीसदी, अभी बिहार का वर्णन चल रहा था, बिहार में नवासी फीसदी लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध नहीं है, पश्चिम बंगाल में 78 फीसदी आबादी को उपलब्ध नहीं है। ऐसे अनेक प्रदेश हैं। मान्यवर, यही हालत टेलीफोन की हैं। अभी संचार क्रांति की बात कही जा रही थी। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम प्रति गांव में प्रत्येक परिवार को फोन देना चाहते हैं, यहां टेलीफोन जाएगा, लेकिन इसमें भी शहरी क्षेत्र में फोन मात्र 26 प्रतिशत है और ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 6 फीसदी है। मान्यवर, विकास की दर को लक्षित किया गया था। आठ फीसदी की बात कही गई थी कि विकास दर बढ़ेगी और विकास दर के आधार पर आम लोगों को उस विकास के अंतर्गत समाहित करते हुए लोगों के जीवन को उन्नति के शिखर पर ले जाने का प्रयत्न किया जाएगा। लेकिन इससे पहले मैंने कहा, वैकल्पिक आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत उन्होंने कहा है, अस्सी को आधार मानकर कहा कि जो अस्सी की विकास दर थी, उसमें इस समय जरूर बढ़ोतरी हुई है। लेकिन उस समय विकास दर 3.5 परसेंट थी, इस समय 6.5 परसेंट तक हम जरूर आ रहे हैं, वैसे 6 पर पूरा नहीं आए हैं, शायद आगे 6.5 परसेंट तक पहुंच जाएं, 8 परसेंट तक पहुंचने की तो कोई संभावना ही नहीं लगती है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहा और आपकी तरफ से प्रश्नों के जवाब में भी यह बात कही गई है कि 6.5 से ज्यादा नहीं जा रहे हैं। लेकिन मान्यवर, यह सब होने के बावजूद भी आम आदमी इसका लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है और इसका कारण यह बताया जा रहा है कि जो वैश्वीकरण, उदारीकरण की तेजी से प्रक्रिया चली है, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला आम किसान सर्वाधिक त्रस्त होगा, इस दौर में आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जिस प्रकार की सब्सिडी की अपेक्षा किसानों को है, वह सब्सिडी किसानों को प्राप्त नहीं हो पाएगी। दुर्दशा यह होगी कि गरीब किसान और प्रताड़ित होगा, गरीब किसान मंहगाई की मार से और ग्रस्त होगा। मान्यवर, विकास दर बढ़ने के साथ-साथ ये आंकड़े जरूर बोलते हैं, लेकिन आंकड़े बोलने के बाद भी जिस ढंग से आम आदमी को लाभान्वित करने की दिशा में कदम बढ़ने चाहिएं वे नहीं हो पा रहे हैं।

इतना ही नहीं, रोजगार की बात कही गई, यह कहा गया है कि सर्वाधिक रोजगार दिलवाया जाएगा। आज पूरे हिंदुस्तान में बेकार नौजवानों की फौज खड़ी हुई है। लोग अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे अपने जीवन का भरण-पोषण कर सकें। जीवन-यापन करने के लिए ऐसे-ऐसे तरीके भी अपनाए जा रहे हैं, जो अवांछित हैं,

4.00 म०प०

असामाजिक भी हैं, लेकिन उन्हें मजबूरी में यह करना पड़ रहा है। सरकार घोषणा कर रही है कि हम बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेंगे। मान्यवर, सामान्य बजट के भाषण के अंतर्गत वित्त मंत्री महोदय ने भी कहा है, इन्होंने कुछ स्रोत भी बताए हैं कि रोजगार का सृजन कहां से होगा। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से ढाई लाख तक का रोजगार हम सृजित करेंगे, लेकिन इसके लिए धन का जो आवंटन किया है, उस धन के आवंटन के माध्यम से और जो रोजगार का सृजन होगा, उसमें कितने लोग आ पाएंगे, इसके कहीं कारगर और ठोस स्वरूप का वर्णन नहीं है। इसी तरीके से कहा गया है कि टेक्सटाइल के माध्यम से भी रोजगार का सृजन होगा, टेक्सटाइल में रोजगार सृजन करने की बड़ी क्षमता है, लेकिन किस तरीके से टेक्सटाइल के माध्यम से रोजगार का सृजन करते हुए लोगों को लगाया जा सकेगा? इसमें यह भी कहा गया है कि लगभग सवा करोड़ लोगों को रोजगार टेक्सटाइल के माध्यम से दिलवाया जा सकता है। यह दिलवाया जा सकता है, लेकिन व्यवस्था कैसे हो सकती है? देश के अंदर लगभग ग्यारह करोड़ बेकार नौजवान हैं और पंजीकरण लगभग साढ़े चार करोड़ के आसपास है। यह एक बहुत बडी तादाद है। अगर इन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो हालत बहुत खराब हो जाएगी। महोदय, स्किल्ड और अनस्किल्ड, दोनों प्रकार के रोजगार प्राप्त करने वाले लोग हैं। दोनों पेरशान हैं। यह बात सही है कि यह कहा गया है कि रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से परिवार के एक-एक व्यक्ति को सौ दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। पच्चीस करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे की जिन्दगी व्यतीत करने वाले हैं। अगर लोगों को एक परिवार को रोजगार दिलाने की बात कही जाती है। पांच करोड़ लोगों को भी सौ दिन के हिसाब से रोजगार दिलवाते हैं, तो पांच करोड़ को पैंसठ रुपए के हिसाब से आंकड़े लगाते हैं तो बत्तीस हजार करोड़ रुपए की जरूरत है।

मान्यवर, 32,000 करोड़ रुपए की जरूरत है लकिन 32,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? यहां बजट के अंदर केवल 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, वह कहां से मिलेगा? तो एक अजीब प्रकार का सपना दिखाने का प्रयत्न किया गया है। इन लोगों को कहां से रोजगार मिलेगा, इसके लिए गंभीरता के साथ योजना के जो प्रारूप बनने चाहिए, उनका अभाव दिखाई पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अनेक आर्थिक अनियमितताओं के कारण और भी परेशानियां बढ़ गई हैं। स्वयं वित्त विभाग के अंदर जो CAG की रिपोर्ट है, CAG की रिपोर्ट के हिसाब से वर्ष 2005 तक 41,000 उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थे और इनमें लगभग 10,52,756 करोड़ रुपए की धनराशि का ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ। उसका उपयोग हुआ या नहीं हुआ, इसकी जानकारी नहीं है। अब वित्त मंत्री जी, इकनॉमिक रेगुलेटरी लाने

की दृष्टि से कौन सी प्रक्रिया अपना रहे हैं, किस ढंग से जा रहे हैं, यह तो वे जानें, लेकिन अगर इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, इकनॉमिक रेगुलेटरी लाने का प्रयत्न नहीं किया गया, विभिन्न विभागों से यूटिलिटि रिपोर्ट प्राप्त करने का कारगर प्रयास नहीं किया गया, तो राजस्व प्राप्तियां भी ठीक से नहीं हो पाएंगी। अगर राजस्व प्राप्तियां नहीं हो पाएंगी, तो राजकोषीय घाटा बड़ी तेजी से बढ़ेगा और महंगाई आसमान छूएगी, आर्थिक अव्यवस्था का सृजन होगा और आर्थिक अराजकता बढ़ेगी, जिसका दुष्परिणाम आम जनता झेलेगी। ये सारे चित्र हैं, जिनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से बजट में सुनहरे सपने दिखाने की कोशिश की गई है और कहा गया है कि आम आदमी को केन्द्र में रखकर, उसके अनुरूप हम बजट का आवंटन कर रहे हैं और बजट को व्यवस्थित कर रहे हैं, इससे आम आदमी लाभान्वित नहीं हो पाएगा। आम आदमी और भी दुर्दशा का शिकार हो रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, आधारभूत ढांचे का ध्वस्तीकरण हो रहा है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि आम आदमी के लाभ के लिए हम काम कर रहे हैं। इस हिसाब से ये जो अनुदानों की पूरक मांगें रखी गई हैं, इन मांगों के माध्यम से आम आदमी कितना लाभान्वित हो पाएगा, यह हम नहीं कह सकते। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI E.M. SUDARSHANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Sir, first of all, I would like to congratulate our UPA Government which has taken all the necessary measures in order to rectify the damages done by the earlier Government. This trend has, more or less, been properly maintained in the two Budgets presented by this Government. For example, the Tamil Nadu Government was starving of money, and in the absence of money, they could not do anything. They were not in a position to pay even hundred rupees to its old-age pensioners. They were going to retrench more than one and half lakh employees. They could not undertake any agricultural activities for the welfare of the poor people. They could not channelise the water for the agriculturists. They could not even properly implement the mid-day meal scheme. That Government has completed its four years. They were living in such a situation for the past four years. But in the past one-and-a-half years of the UPA Government, they are flourishing like anything. Every day, they are announcing so many benefits for the agriculturists. Rural road are coming up, new buildings are coming up, mid-day meal scheme is being successfully implemented and children are also being protected. These measures are being

undertaken by the UPA Government, as it is allotting funds properly and proportionately to the State Governments. Especially, after the Twelfth Finance Commission, the State Governments are endowed with a lost of money in hand. Therefore, in this way, they can show that they themselves are doing it. It may appear as if they are doing everything. But we know, the people know, that it is the UPA Government which is doing wonder in just one-and-a-half years. It has done all these things in the past one-and-a-half years. In the same way, we have taken up the small issue of rural telephony. The NDA Government had abandoned this scheme. They had never gone to the villages. But now, the UPA Government is coming forward with the rural telephony for the ordinary man. That is, the *Aam admi* is going to get the telephone. Even small villages are going to be connected by the WLL technology and other schemes which have now been started throughout the country by the UPA Government within one-and-a-half years of its rule.

So far as the fast track courts are concerned, this scheme was not implemented properly during the previous regime. But now we have come forward with Rs. 100 crores in one installment itself to make the fast track courts beneficial for the ordinary people. I can cite many example. For example, we are developing small and medium industries by giving funds to the State Governments. But they are not doing it. I can cite the example of Tamil Nadu where the present Chief Minister is facing cases in SIDCO and TIDCO for mishandling of funds and purchase of property. Even though the UPA Government has given them funds, they could not even lease out the land and they could not give it on outright purchase to small scale industrialists. Even though we are giving funds, the small and medium scale industry is dying in Tamil Nadu because of the mismanagement of the Tamil Nadu Government. The Finance Minister has been appreciated not only by the Corporate sector, but he has been appreciated throughout the world. We have to concentrate on agriculturists. The rate of interest for agriculturists is soaring. So far as the cooperative sector is concerned, it is being dismantled and mismanaged in many places. Therefore, I would request that there should be some mechanism whereby the agriculturists can get the same rate of interest as the industrialists are getting. The ordinary people living in villages should get financial assistance as and when they need it. Thank you.

SHRI CHITTABRATA MAJUMDAR (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, while supporting both the Appropriation Bills, I would like to mention some of its shortcomings. Now flood and soil erosion have become regular features in our country. A good amount is being spent, every year, by the Central Government as well as the State Governments to provide relief to the people. But there is no additional allocation to control floods and soil erosion. That is a very vital area which should not be missed.

The second point is about natural calamities. The recent incident of Mumbai has proved that population in metropolitan cities is increasing day by day, but the drainage system which is there, is not enough to handle the situation. The drainage system in the metropolitan cities should be improved and should be looked into. But no additional allocation has been made for this purpose.

Another point is, the number of cases referred to BRPSE is 35 and the cases recommended by the BRPSE to the Ministry is 15. I find that for revival, practically, no amount has been allocated. A small amount has been allocated for the Hindustan Salt. The Cabinet has cleared the revival of BBJ Construction Co. Ltd.

But there is no mention about any allocation by the Government of India. So, I think that in this area also, if proper allocation is not made for the cases pending before the BRPSE's and for approval by the Government, it would so happen that for want of capital, the industries, which have some scope of revival today, would become sick again as time passes. So, that is another problem. I think, that is also an area that has not been looked into.

Similarly, there are other areas,. I do not want to take much time. But these are some of the vital areas which I think the hon. Finance Minister should look into. Thank you, Sir.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Mr. Deputy Chairman, Sir, I am grateful to the three hon. Members, Shri Kalraj Mishra, Shri Natchiappan and Shri Majumdar, for participating in this brief debate. Let me assure Shri Mishra, each one of the Heads for which I am asking for an additional cash outgo, is a Head, which came up after 28th February, 2005. I could go into them one by one and explain to you.

Take, for example, the Delhi Metro Rail Corporation. Now, when the additional expenditure is projected say, after the fourth week of February, or, the third week of February, it is not possible to include it in the Budget. So, one has to include it at the first opportunity after the Budget. Similarly, take the Fast Track Courts. It is when the Supreme Court delivered a judgement saying that the Fast Track Courts shall be continued beyond the expiry date, that my colleague, the Law Minister, came to the Cabinet and said that they needed money to continue them. The Central Government is fully funding them now for continuation and therefore, Rs. 100 crores were needed.

I can go down the list, item by item. Every one of them is an item that came up after the Budget was presented, and, therefore, there is nothing unusual in a supplementary Budget being presented. It has been done in the past, and.,I am afraid, it will be done in the future also.

Sir, sometimes I wonder, are we talking about two different economies? In fact, the performance of India's economy in the current fiscal is considerably better than last year, and last year's performance was, by all accounts, a very creditable performance. Inflation is down to 3.84 per cent–the lowest, not in one year, but lowest for the last two years, that is, for the period when the UPA has been in the Government and for the last year of the NDA Government.

There are foreign exchange reserves of 142 billion dollars. Manufacturing is growing by 11.7 per. cent. The industrial sector in April, May and June has recorded double-digit growth of over ten per cent. Agriculture, this year, will do better. Thirty-one out of thirty-six meteorological divisions have reported excess or normal rainfall and we still have another couple of weeks before the South-West Monsoon period is over. So, I think we should not wish ourselves bad luck; we should wish ourselves good luck, especially when the circumstances are good, our workers are working hard, our farmers are working hard and our service-providers are working hard. All in all, let me assure Shri Mishra that growth this year will be higher than growth last year, given the first quarter's figures.

Sir, as far as job creation is concerned, job creation is a function of economic growth. When, for example, in 2002-03, thanks to a bad

monsoon, the economy grew by four per cent, during the NDA Government, not many jobs were created. But, in the subsequent year, thanks to a bountiful monsoon, and, I think, 102 per cent of normal rainfall, in 2003-04, agriculture sector bounced back and that gave you 8.5 per cent growth; jobs were created. Well, last year, we had a deficient monsoon. Nevertheless, I believe adequate jobs were created, thanks to the buoyancy in the industry sector and the services sector, which performed better than in the last year of the NDA Government.

This year, all the three sectors and doing better than last year. Therefore, at the end of the year, when job creation figures are available to the Government and I will present them to Parliament. I am absolutely confident that more jobs will be created in 2005-06 than in the previous two years.

Mr. Natchiappan is absolutely right that States are flush with funds. There is not a single State today in overdraft. I think, there is only one State which had a ways and means advance and even that, I think, is being squared in a few days. Every State is flush with funds. There are States with Cash Reserves and Cash Balance of Rs. 3000 crore on the 1st of August. There are half a dozen States with a Cash Balance of Rs. 2000 crore. Why? The twelfth Finance Commission has been extremely generous to States. That is why we have written to the all State Government 'spend now'. This is the time to spend. Spend on Plan and quicken the pace of expenditure so that at the end of the year you will have better results. Earlier practice of not being able to spend for the first six months, we should abandon that practice, because money has been made available even in the First Quarter by way of normal Central assistance and additional Central assistance. Every State today seems to be flush with funds. We must quicken the pace of spending so that results are visible at the end of the year.

Sir, I take Mr. Majumdar's point on soil erosion, drainage system, etc. I will certainly convey it to my colleagues in the respective Ministries. But enough money is provided. Money is not a constraint this year. That is the only message that I want to give in this brief reply.

On BRPSE, please remember that this is an institution that was put in place by the UPA Government. It is for the reconstruction of sick public sectors. Look at the choice of the world 'Reconstruction'.

We are not simply reviving; we are not simply restructuring, but we are reconstructing the sick public sector. But there are only a certain number of sick industries which can be reconstructed. Some are too sick and nothing can be done about them. We must simply summon the courage and resolve to wind them up, as we are doing in some of the States. A totally sick industry is drain on resources. But you are right. We have identified a number of sick industries which, we believe, can be reconstructed. These have been referred to the BRPSE. The BRPSE has made its recommendations. Each of these cases will have to go to the administrative Ministry. Then, it has to come by way of a Cabinet Note to the CCEA, and the CCEA would have to take a final decision. You yourself mentioned that we have taken decisions in a couple of cases. As and when these cases come to the Cabinet Committee, we will take appropriate decisions. But our intention is to reconstruct and revive and put on the rails those sick industries which can be revived. Sir, we need money for this. In the last year and now, if I recall, we have given Rs. 550 crore, last September-October for payment of salaries and statutory dues of public sector workers which had not been paid for many months. Some of them, I think, were then able to pay on their own I think, about six were able to pay on their own. But that still left a large number. Again, as you know, after this Budget was presented, we gave another Rs. 141 crore to pay the unpaid wages. We cannot go on paying unpaid wages in industries which are not working. Therefore, it is wise to take a decision whether an industry can be revived or not. Let me assure this House, wherever an industry can be revived and put on the rails we, will revive it. Money will not be a constraint for that as long as the revival plan is a feasible and viable plan. Sir, that is why we have created the National Investment Fund. The Fund has received wide approval. The minor controversy lies where to find the money to put into that Fund. But I am sure that we can resolve that issue in due course. This Fund will be created. The corpus of the fund will not be touched. This Fund will be invested through public sector managers. Returns from the Fund, as the Cabinet Note says, will be used for capital investment in viable and revivable sick public sector undertakings.

Therefore, Mr. Mazumdar need not fear. Whichever sick industry can be revived, this Government will revive. I am glad I have had an opportunity, while replying to this debate, to clarify this position. Sir, I think I have answered most of the points. Others, we have taken note of. We will pass these on to the concerned Ministers and I am sure they will either respond at a suitable time or they will write letters.

I request that the Bill be returned.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

That the Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2005-06, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall not take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2, 3 *and the Schedule were added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I beg to move:

That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

That the Bill to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 2003, in excess of the amounts granted for those services and for that year, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

The concerned Ministers and I am sure they will either respond at a suitable time or they will write letters.

I request that the Bill be returned.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

That the Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2005-06, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2, 3 *and the Schedule were added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I beg to move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

That the Bill to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 2003, in excess of the amounts granted for those services and for that year, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2, 3 *and the Schedule were added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I beg to move:

That the Bill be returned.

The question was put and the motion was adopted.

STATEMENT BY MINISTER

Status of Implementation of the recommendations contained in Fifth and Ninth Reports of the department related Parliamentary Standing Committee on Finance

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS (SHRI PREM CHAND GUPTA): Sir, I am making this statement on the status of implementation of recommendations contained in the Fifth and Ninth Reports of the Standing committee on Finance in pursuance of directions of the hon. Chairman, Rajya Sabha issued *vide* Rajya Sabha bulletin part-II, dated 28th September, 2004.

In all, five recommendations were made by the Committee in the two Reports where action is required on the part of the Government. These recommendations pertain to comprehensive review of the Companies, Act, 1956, filling up the vacancies in the company Law Board, Serious Fraud Investigation Office and strengthening the Inspection wing in the Ministry.

The present status of implementation of the various recommendations made by the Committee is indicated in the Annexures to my statement, which is laid on the Table of the House. I would not like to take the valuable time of the House to read out all the contents of these Annexures. I would request that this may be considered as read.